शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 अप्रैल 2018
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

बड़वानी जिले के आदिवासियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

अजय ठाकुर (शोधार्थी)
वाणिज्य अध्ययन शाला
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
डॉ. अशोक वर्मा (प्राचार्य)
शा. महाविद्यालय, निवाली, (बड़वानी)
डॉ. प्रीति सिंह (विभागाध्यक्ष)
वाणिज्य अध्ययन शाला
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
इन्दौर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

बड़वानी जिला मध्यप्रदेश का एक कृषि प्रधान तथा जनजातीय बहुलता वाला जिला है जहाँ 70 प्रतिशत से अधिक लोगों का मुखय व्यवसाय कृषि है। चूंकि बड़वानी जिला मध्यप्रदेश का एक कृषि प्रधान जिला है, जहाँ के कृषक आज भी अशिक्षित एवं निर्धन हैं तथा जिनके खेत छोटे एवं बिखरे हैं। इन कारणों से यहाँ की कृषि, अभी तक कृषि विज्ञान से कोई लाभ नही उठा पाई है अतः वर्तमान में भी कृषि परम्परागत प्रणाली पर आधारित है जो इनकी आर्थिक प्रगति का मूल कारण है।

कुंजी शब्द : *कृषि विकास, आर्थिक स्थिति, फसल उत्पादन, वनोपज इत्यादि।*

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है। जहाँ पर आदि मानव के युग से लेकर आधुनिक युग तक सभी युगों में कृषि होती आ रही है। आदि मानव अपनी क्षुधापूर्ति के लिए पहले शिकार करता था और जंगल से कंदमूल आदि प्राप्त करता था। फिर उसने धीरे-धीरे एक स्थान पर रहना सीखा और जहाँ पर वह रहता था वहाँ पर कृषि करना प्रारम्भ कर दिया। वहीं से कृषि की शुरूआत हुई।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ दशकों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं तथा पिछले कई दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि रही है। देश की 70 प्रतिशत जनसंखया गावों में निवास करती है जिसमें से 90 प्रतिशत जनसँख्या कृषि तथा उससे संबन्धित कार्यो में जुड़ी हुई है। ऐसे मे कृषि तथा कृषि से संबन्धित सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत विभिन्न फसलों जैसे - खाद्य, व्यापारिक, दलहन व तिलहन आदि के विपणन प्रबंध के महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्य करना आवश्यक है। आज अगर देखा जाए तो कृषि के अभाव में सब कुछ असम्भव है। जिस प्रकार 'बिना पानी सब सून' उसी प्रकार बिना कृषि के देश की अर्थव्यवस्था कुछ भी नही है। हमें अपनी दैनिक

जीवन की आवश्यकता पूर्ति में सबसे पहले कृषि उपज पर ही निर्भर रहना पडता है। मनुष्य को रोटी कपडा और मकान की आवश्यकता होती है। उसमें भी वह बिना वस्त्र और मकान के जीवित रह सकता है, किन्तु रोटी के बिना कभी नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे वह अमीर हो या गरीब खाता तो रोटी ही है।

हमारे देश में तरह-तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है जैसे- गेंहू, चावल, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, गन्ना, चना एवं अनेक प्रकार की दालें तथा सब्जियाँ इत्यादी। भारत में मध्यप्रदेश को सोयाबीन का प्रथम उत्पादक प्रदेश माना जाता है। बडवानी जिले की मुखय फसलें- मक्का, गेंहू, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, बाजरा तथा चावल इत्यादि है। यहां पर सब्जियों का उत्पादन विशेष तौर पर किया जाता है, जिसमें लाल मिर्ची प्रमुख है। किसान अपनी मौसमी फसलों का उत्पादन कर लेने के बाद सब्जियों का भी उत्पादन करता है।

देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संखया में धार, झाबुआ, अलीराजपूर के बाद बडवानी का ही स्थान है। बड़वानी जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अतः कृषि देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसी प्रकार आवश्यक है, जिस प्रकार एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है।

प्राचीन काल में यहाँ के जनजातीय कृषकों द्वारा केवल खाद्य आपूर्ति हेतु कृषि उत्पादन किया जाता था। धीरे-धीरे आवश्यकताएं बढ़ती गई तथा अपनी बढ़ती जरूरतों की आपूर्ति हेतु उनके द्वारा खाद्य व नगदी फसलों का उत्पादन किया जाने लगा। विपणन के बढ़ते महत्वपूर्ण पहलुओं का ज्ञान हुआ तथा अधिकाधिक नगदी फसलों की कृषि की जाने लगी। अधिक लाभ के कारण यहाँ के कृषकों की आर्थिक स्थिति मे परिवर्तन होने लगा, किन्तु आज भी बड़वानी जिले के लोग अशिक्षा से जूझ रहे हैं तथा भारतीय विपणन प्रणाली की नई-नई योजनाओं से अछूते हैं। इस प्रकार शिक्षा के अभाव के कारण यहाँ के लोगो की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति में बाधा उत्पन्न हो रही है। इन्ही महत्वपूर्ण पहलुओं के अध्ययन हेतु इस क्षेत्र के विपणन पहलूओं का अध्ययन महसूस हुआ तथा शोध हेतु उपर्युक्त शोध विषय का चयन किया गया।

साहित्य की समीक्षा

पालीवाल चन्द्रमोहन 1989 आदिवासी हरिजन आर्थिक विकास (बस्तर जिले के संदर्भ में), नर्मदा बुक सेंटर, नई दिल्ली, इलाहाबाद पृष्ठ 22 ने अपने अध्ययन मे यह बताया है कि जनजातीय लोग अशिक्षा, अज्ञानता व कंपनियों के कम प्रचार-प्रसार के कारण उन्नत बीजों व खादों का सही अनुपात मे उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे लाभ नही मिल पाता है। श्रीवास्तव ए.आर.एन.2020 (जनजातीय संस्कृति मध्यप्रदेश), हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल पृष्ठ 12-13 ने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि जनजातीय बाजार सामान्य एवं बड़े-बड़े बाजारों के साथ सम्बंधित हो गया है, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में काफी नयापन आ गया है। जनजातीय लोग आधुनिक फैशन तथा आराम की वस्तुएं बाहर से खरीदने लगे हैं। इसके साथ ही आदिवासी अर्थव्यवस्था की वस्तुएं भी बाजारों में अच्छी कीमत पाने लगी हैं। जनजातीय आर्थिक गतिविधियों को काफी प्रोत्साहित किया गया है। भील तथा बारेला आलू, प्याज व नये प्रकार की सब्जियों की खेती करने लगे हैं तथा उसे साप्ताहिक बाजार में बेचने लगे हैं। कारीगर वर्ग

की जनजातियाँ उन बनाये हुए सामानों को अपने लोगो के बीच नहीं बेचती वरन् स्थानीय बाजार में थोक रूप मे भी बेचते हैं। सहकारी आन्दोलन ने इन आर्थिक पहलूओं को नया मोड़ दिया है। कृषक सहकारी समितीयों से उन्नत बीज एवं रासायनिक खाद प्राप्त करने लगे हैं। लवानिया एम.एम एवं जैन 2007 ग्रामीण समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा पृष्ठ 58 के अनुसार किसान के पास जो खेती संबंधी औजार होते हैं, अधिकतर पुराने ढंग के होते हैं या तो उनको अच्छी हालात में रखा जाये या यदि वे बिल्कुल पुराने हो गये हों तो उनकी जगह नये औजार खरीद लिए जाएँ, तो खेती अच्छे ढंग से की जा सकती है। परन्तु किसान के पास जहां पशु खरीदने की समस्या होती, वहीं हल इत्यादि के लिए भी समस्या होती है। यदि उनका हल टूट जाता है या उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट जाता है और उनको नया पहिया खरीदना होता है, तो उन्हें महाजन के पास जाकर रूपया उधार लेने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहता है।

शुक्ल हीरालाल 1997 आदिवासी अस्मिता और विकास हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल पृष्ठ 22 ने अपनी पुस्तक के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश के आदिवासियों की आय का प्रमुख स्रोत है जंगली उत्पादों का संचय और विक्रय, कृषि, मत्स्यपालन, जंगलो में मजदूरी इत्यादि है। ये लोग विभिन्न प्रकार की उपजों का संग्रहण करके पास के बाजारों में कम दामों पर बेचने के लिए बाध्य होते हैं। चूंकि बाजार दर और विभिन्न प्रकार के बाजार हथकंडों आदि से ये अपरिचित होते हैं। अतएव उन्हें कम कीमतों पर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ठीक इसके विपरित जब वह बाजार से उसकी जरूरत की वस्तुएं खरीदता है तो उसे अधिक मूल्य देना पड़ता है।

उद्देश्य

बड़वानी जिले के आदिवासियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

बड़वानी जिले के आदिवासियों की मूल आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना।

परिकल्पना

बड़वानी जिले के आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है।

बड़वानी जिले के आदिवासी अब शिक्षित होने लगे हैं।

प्रविधि

प्रस्तुत शोध विवरणात्मक अध्ययन पर आधारित है। अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है तथा सर्वेक्षण में बड़वानी जिले की 8 तहसीलों के 400 किसानों को लिया गया है।

प्रस्तुत शोध विषय के विश्लेषण में गहनता व सूक्ष्मता लाने तथा सही निष्कर्ष की प्राप्ति की दृष्टि से अध्ययन के क्षेत्र को बड़वानी जिले तक सीमित रखा गया है। शोध का चयन करते समय, समय सीमा का ध्यान रखते हुये 2013 से 2017 तक, बड़वानी जिले के कृषि उत्पादन एवं वनोपज का आदिवासियों की आर्थिक प्रगति में भूमिका का अध्ययन किया गया है तथा प्रस्तुत शोध अध्ययन में समस्या, सुझाव एवं निष्कर्ष बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में दिये गये हैं।

आर्थिक विश्लेषण

क्या आपके पास कृषि भूमि है ? यदि है तो (एकड़ में) कितनी ?

कृषि भूमि (एकड़ में)	कुल उत्तरदाता	प्रतिशत
1-5	280	70%
5-10	60	15%
10-15	40	10%
15-20	20	5%
योग	400	100%

स्रोत- सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बड़वानी जिले के 70 %किसानों के पास 1-5 एकड़ कृषि भूमि है, 15% किसानों के पास 5-10 एकड़ कृषि भूमि है, 10% किसान के पास 10-15 एकड़ कृषि भूमि है, तथा 5% किसान के पास 15-20 एकड़ कृषि भूमि है। अतः स्पष्ट है कि 70% आदिवासी किसान छोटे हैं तथा बड़े किसानों का प्रतिशत सबसे कम जो कि 5% है।

क्या आप शिक्षित हैं ? यदि है तो शिक्षा का स्तर क्या है।

शिक्षा	कुल उत्तरदाता	प्रतिशत
प्राथमिक	85	21.25%
माध्यमिक	55	13.75%
हाईस्कूल	50	12.5%
हायर सेकण्डरी	20	5%
निरक्षर	190	47.5%
योग	400	100%

स्रोत - सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त सर्वेक्षण के अनुसार 21.25% किसानों ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। 13.75% किसानों ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है। 12.5% किसानों ने हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्त की है। 5% किसानों ने हायर सेकण्डरी शिक्षा प्राप्त की है। सर्वाधिक प्रतिशत किसान 47.5% जो कि स्कूल दूरी पर होने, अत्यधिक कृषि कार्य होने, परिवार में किसी अन्य के शिक्षित नहीं होने के कारण इनके माता-पिता बच्चों को पढ़ाने मे रूचि नही रखते हैं। इसी कारण से निरक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है।

संपूर्ण वर्ष के दौरान उत्पदन प्रति एकड़ में कितना क्विंटल होता है ?

उत्पदन प्रति एकड क्विं	कुल उत्तरदाता	प्रतिशत
10-15 क्विं.	240	60%
15-30 क्विं.	110	27.5%
30-40 क्वि.	30	7.5%
40-50 क्वि	20	5%
योग	400	100%

स्रोत : - सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण वर्ष के दौरान 60% किसान 10-15 क्विं. प्रति एकड उत्पादन करते हैं, 27.5% किसान 15-30 क्विं. प्रति एकड उत्पादन करते हैं, 7.5% किसान 30=40 क्विं. प्रति एकड उत्पादन करते हैं, 5% किसान 40-50 क्वि प्रति एकड उत्पादन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि 60% आदिवासी किसानों का उत्पादन कम मात्रा 10-15 क्विं प्रति एकड में होता है तथा 40-50 क्वी किसानों का प्रति एकड उत्पादन अधिक मात्रा में होता है।

क्या आपको अपनी फसलों का पर्याप्त लाभ मिल रहा है? हॉ/नहीं

हाँ/नहीं	कुल उत्तरदाता	प्रतिशत
हाँ	40	10%
नही	360	90%
योग	400	100%

स्त्रोतः- सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 10% आदिवासी किसानों को उनके कृषि उत्पादन का पर्याप्त लाभ मिल रहा है तथा 90% आदिवासी किसानों को उनके कृषि उत्पादन का पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है।

आपको फसलों के उत्पादन में लागत अधिक आती है? हॉ/नहीं

हाँ/नहीं	कुल उत्तरदाता	प्रतिशत
हाँ	290	72.5%
नही	110	27.5%
योग	400	100%

स्त्रोतः- सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 72.5% आदिवासी किसानों को उनके कृषि उत्पादन में लागत अधिक आती है तथा 27.5% आदिवासी किसानों को उनके कृषि उत्पादन में लागत कम आती है।

बीज कहाँ से प्राप्त होता है ?

बीज क्रय स्रोत	कुल उत्तरदाता	प्रतिशत
बीज निगम से	70	17.5%
बीज कंपनी	160	40%
साहूकार से	110	27.5%
स्वयं तैयार करते है	60	15%
योग	400	100%

स्रोत :- सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि आदिवासी किसानों में से 17.5% तथा 15% किसान जिनका प्रतिशत कम है अपने कृषि उत्पादन के लिए बीज क्रमशः बीज निगम से तथा स्वयं तैयार करते हैं, जिसकी लागत कम होती है तथा 40% और 27.5% किसान जिनका प्रतिशत अधिक है। अपने कृषि

उत्पादन के लिए बीज क्रमश: बीज कंपनी से तथा साहूकारों से प्राप्त करते है जिसकी लागत अधिक होती है।

आप कृषि हेतु खाद तथा रासायनिक दवाईयाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं ?

क्रय स्रोत खाद	कुल उत्तरदाता	प्रतिशत
सरकार से	100	25%
कंपनी	80	20%
साहूकार से	140	35%
स्वयं तैयार करते हैं	80	20%
योग	400	100%

स्रोत : सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि आदिवासी किसानों में से 25%तथा 20% किसान जिनका प्रतिशत कम है अपने कृषि उत्पादन के लिए खाद व रासायनिक दवाईयॉ क्रमश: सरकार से तथा स्वयं तैयार करते हैं, जिसकी लागत कम आती है तथा 20% और 35% किसान जिनका प्रतिशत अधिक है अपने कृषि उत्पादन के लिए खाद व रासायनिक दवाईयॉ क्रमश: कंपनी से तथा साहूकारों से प्राप्त करते हैं, जिसकी लागत अधिक होती है।

क्या आपने पिछले 5 वर्षो में एक वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया है ? हाँ तो कहाँ से

ऋण स्रोत	उत्तरदाता	प्रतिशत
कृषि बैंक	150	37.5%
महाजन	70	17.5%
साहूकार	90	22.5%
अन्य परिचित	90	22.5%
योग	400	100%

स्रोत - सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बड़वानी जिले के आदिवासी किसानों में से 37.5% किसानों ने जिनका प्रतिशत कम है, कृषि कार्य के लिए कृषि बैंक से त्रण प्राप्त करते हैं, जिसकी ब्याज की दर कम होती है तथा अन्य सभी जिनका प्रतिशत अधिक है महाजन, साहूकार तथा अन्य परिचित से ऋण प्राप्त करते हैं, जिसकी ब्याज की दर अधिक होती है।

क्या आपको पशुपालन से आय प्राप्त होती है। हाँ / नहीं

हाँ/नहीं	कुल उत्तरदाता	प्रतिशत
हॉ	80	20%
नही	320	80%
योग	400	100%

स्रोत - सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बड़वानी जिले के आदिवासी किसानों में से 80% किसानों ने जिनका प्रतिशत अधिक है, पशुपालन से आय प्राप्त नहीं होती है तथा अन्य 20% किसान जिनका प्रतिशत कम है, को पशुपालन से आय प्राप्त होती है।

क्या आपकी संपूर्ण वर्ष के दौरान बचत होती हैं? हाँ / नहीं

हाँ/नहीं	कुल उत्तरदाता	प्रतिशत
हॉ	160	40%
नही	240	60%
योग	400	100%

स्रोत - सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बड़वानी जिले के आदिवासी किसानों में से 60% किसानों को जिनका प्रतिशत अधिक है, को संपूर्ण वर्ष के दौरान बचत नहीं होती है तथा अन्य 40% किसान जिनका प्रतिशत कम है, को संपूर्ण वर्ष के दौरान बचत होती है।

बचत के लिए प्राथमिक बाधा क्या हैं ?

बाधाएं	कुल उत्तरदाता	प्रतिशत
खर्च अधिक	30	7.5%
लागत अधिक	50	12.5%
कम उत्पादन	40	10%
कम कीमत मिलना	110	27.5%
उपरोक्त सभी	170	42.5%
योग	400	100%

स्रोत - सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बड़वानी जिले के आदिवासी किसानों में से 7.5% किसानों का कहना है कि उनका खर्चे अधिक है। 12.5% का कहना है कि लागत अधिक होती है, 10% कहते हैं कि उत्पादन कम होता है, 27.5% ऐसे हैं जिन्हें कम कीमत मिलती है तथा 42.5% ऐसे हैं जिन्हें उपर्युक्त कारणों से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है।

क्या आपको कृषि हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, उसका पर्याप्त लाभ मिल रहा है ?

हाँ/नहीं	कुल उत्तरदाता	प्रतिशत
हॉ	150	37%
नही	250	62.5%
योग	400	100%

स्रोत - सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बड़वानी जिले के आदिवासी किसानों में से 37% किसानों को कृषि हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, उसका पर्याप्त लाभ मिल रहा है तथा 62.5% किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

परिकल्पना का स्पष्टीकरण

बड़वानी जिलें के आदिवासीयों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है।

संबन्धित शोध साहित्य का अध्ययन, साक्षात्कार एवं सामूहिक चर्चा करने से प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बड़वानी जिले के किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनकी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः हमारी यह परिकल्पना अपनी कसौटी पर खरी नहीं उतरी है।

सुझाव

बड़वानी जिले के आदिवासीयों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए।

बड़वानी जिले के आदिवासी अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आदिवासी क्षेत्र के बाहर रोजगार के अवसर खोजने के लिए बाध्य हैं। अतः बड़वानी जिले में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किये जाना चाहिए।

बड़वानी जिलें के आदिवासी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके इसके लिए उन्हें अपनी कुल आय का कुछ भाग बचत में रखना चाहिए, जिसे वह समय आने पर बीज, खाद एवं रासायनिक दवाईयाँ क्रय करने के लिये उपयोग कर सके, जिससे वह महाजनों को अनुचित ब्याज के भुगतान से बच सकते हैं।

बड़वानी जिले के आदिवासी अब शिक्षित होने लगे हैं।

संबन्धित शोध साहित्य का अध्ययन, साक्षात्कार एवं सामूहिक चर्चा करने से प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बड़वानी जिले के जनजातीय लोग अशिक्षा, अज्ञानता व कंपनियों के कम प्रचार-प्रसार के कारण उन्नत बीजों व खादों का सही अनुपात मे उपयोग नही कर पाते हैं, जिससे लाभ नहीं मिल पाता है। जिसके कारण उनकी आर्थकि स्थिति वैसी कि वैसी ही है। अतः हमारी यह परिकल्पना अपनी कसौटी पर खरी नहीं उतरी है।

जनजातीय लोग अशिक्षा, अज्ञानता व कंपनियों के कम प्रचार-प्रसार के कारण उन्नत बीजों व खादों का सही अनुपात मे उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे लाभ नहीं मिल पाता है। अतः सरकार द्वारा उन्नत बीजों व खादों का सही अनुपात मे उपयोग का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाना चाहिए।

इस क्षेत्र में प्रत्येक तहसील स्तर पर उन्नत बीजों व खादों का सही अनुपात मे उपयोग का समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

संबंधित साहित्य सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात यह बात सामने आई है कि विभिन्न विद्वानों ने आदिवासी क्षेत्र में किसानों की आर्थिक स्थिति के संबंध में विभिन्न पहलूओं का अध्ययन किया है। कुछ विद्वानों ने इन क्षेत्रों के परम्परागत व्यवासाय के संबंध में अपना मत व्यक्त

किया है तो कुछ विद्वानों ने कृषि क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन किसी भी विद्वान ने कृषि विपणन व्यवस्था के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को छुआ तक नहीं। इन सब पहलूओं का अध्ययन ही हमारा उद्देश्य है। इस प्रकार यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि धनी लोग जैसे साहूकार एवं महाजन लालच देकर आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसा देते हैं और कर्ज वापस नहीं कर पाने की स्थिति में उन्हें बंधुआ विक्रेता की तरह अपना समस्त कृषि उत्पादन कम मूल्य पर विक्रय करने के लिए बाध्य करने में भी पीछे नहीं हटते हैं और उनका निरंतर शोषण किया जाता है। अतः बड़वानी जिले के आदिवासी कृषकों की आर्थिक प्रगति नही हो पा रही है।

संदर्भ ग्रन्थ

- *पालीवाल चन्द्रमोहन 1989 आदिवासी हरिजन आर्थिक विकास (बस्तर जिले के संदर्भ में), नर्मदा बुक सेंटर नई दिल्ली, इलाहाबाद पृष्ठ 22*
- *श्रीवास्तव ए.आ.एन.2002 (जनजातीय संस्कृति मध्यप्रदेश), हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल पृष्ठ 12-13*
- *लवानिया एम.एम एवं जैन 2007 ग्रामीण समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा पृष्ठ 58*
- *शुक्ल हीरालाल 1997 आदिवासी अस्मिता और विकास हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल पृष्ठ 22*
- *वार्षिक : वार्षिक मनोरमा ईयर बुक 2012-13*
- *डॉ. ब्रम्हदेव शर्मा २०१२ आदिवासी विकास एक सैद्धांतिक विवेचन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा भोपाल पृष्ठ 185*